



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 30 मार्च, 2010/9 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 29th March, 2010

No. Shram (B) 1- 3/ 2005-Estt.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under section- 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act no. 14 of 1947) and in consultation with the Hon'ble High Court, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri A. S. Jaswal presently posted as Registrar (Rules), High Court of Himachal Pradesh and Shri Chirag Bhanu Singh, presently posted as Additional District and Sessions Judge, Una as Presiding Officer of the Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla and Kangra at Dharamshala respectively on deputation basis with immediate effect. The period of deputation will be two years in the first instance.

Their deputation period will be governed by the terms and conditions of deputation as specified by the Hon'ble High Court vide letter No. HHC/Admn. 28 (27)80-1530 dated 7th December, 1989 from the Registrar, Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to relieve Sh. J. S. Mahantan, Presiding Officer, Labour Court-Industrial Tribunal, Shimla to enable him to join his new assignment.

By order,
ANIL KHACHI
Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 199/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गाहलियां, तहसील कांगडा, जिला कांगडा में रानीताल कोटला सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ० क्षेत्र) कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगडा	कांगडा	गाहलियां	1294 / 1	0—00—34
			1295 / 1	0—00—13
			1296 / 1	0—00—06
			1297 / 1	0—00—03
			1299 / 1	0—00—88
			कुल किता 5	0—01—44

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 165/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ठण्डोल, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा मे भवारना—जससिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कांगडा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगडा	पालमपुर	ठण्डोल	2525 / 1	0—07—29
			2528 / 1	0—00—12
			2532 / 1	0—06—03
			2846 / 24621 / 1	0—00—82
			कुल किता 4	0—14—26

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)155/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मालनू, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा मे भवारना—जससिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है ,उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ० क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगडा	पालमपुर	मालनू	158 / 1	0-00-10
			159 / 1	0-00-84
			1230 / 164 / 1	0-00-06
			166 / 1	0-00-46
			167 / 1	0-00-16
			168 / 1	0-00-52
			260 / 1	0-00-14
			297	0-00-28
कुल किता 8			0-02-56	

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 204 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अन्द्रेटा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा में रानीताल कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ० क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगडा	कांगड़ा	अन्द्रेटा	111 / 1	0-00-30
			112 / 1	0-00-40
			113	0-00-19
			133 / 1	0-00-26
			136 / 1	0-00-36
			571 / 1	0-01-24
			567 / 1	0-00-26
			566 / 1	0-00-64
			572 / 1	0-00-17
			576	0-02-67
			708 / 1	0-00-24
			709 / 1	0-00-14
कुल किता			12	0-06-87

शिमला-2, 27 मार्च, 2010

सं० पी०बी०डब्ल्यू०बी०एफ०(5) 28/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव क्यारवी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में गुम्मा जासल वांया क्यारवी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द० क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द० क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
शिमला	कोटखाई	क्यारवी	365 / 1	0-07-18
			358 / 1	0-01-46
			किता 2	0-08-64

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ०—(5) 172/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव श्यामपुर गोरखूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में पांवटा भगानी सड़क के निर्माण हेतु अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन सम्राहता, लोक निर्माण विभाग शिमला, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (विघा विस्वा)
सिरमौर	पांवटा साहिब	श्यामपुर गोरखूवाला	254	17-6
			275	1-4
		कुल जोड़	किता-2	18-10

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 मार्च, 2010

संख्या ई.एक्स.एन-एफ(10)-1/2010.—हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसरण में, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में प्रारूप संशोधनों को इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-1/2010(i) तारीख 11-03-2010 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12-03-2010 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्याक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I में प्रथम अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

संशोधन

“अनुसूची-I का संशोधन :—

अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 की मद के सामने उप-मद (क), (ख), (ग), और (घ) की स्तम्भ संख्या 3 के नीचे विद्यमान अंकों, चिन्हों और शब्दों “120/—रुपए”, “100/— रुपए”, “50/— रुपए” और “40/—रुपए” के स्थान पर क्रमशः “240/रुपए”, “150/—रुपए”, “75/—/रुपए” और “60/—रुपए” अंक , चिन्ह और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।”।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2010 dated 29th March, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th March, 2010

No. EXN-F(10)-1/2010.—Whereas in pursuance to the provisions of Section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) the draft amendments in Schedule-I appended to the said Act, were published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 12th March, 2010 vide this department notification No.EXN-F(10)-1/2010(i) dated 11.3.2010, for inviting objections and suggestions from the person (s) likely to be affected thereby;

And whereas in this behalf, no objection(s)/suggestion(s) have been received within the stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in Schedule-I appended to the aforesaid Act, w.e.f. 1st April, 2010, namely:—

AMENDMENTS

“Amendment of Schedule-I :—

In Schedule-I, against item at Sr. No. 1, sub-items (a), (b), (c) and (d) below column No. 3 for the existing words, signs and figures “Rs. 120/-”, “Rs.100/-”, “Rs.50/-” and “Rs.40/-”, the

words, signs and figures “Rs. 240/-” , “Rs.150/-“, Rs.75/-“ and “Rs. 60/-”, shall be substituted, respectively.”

By order,
Sd/-
Principal Secretary.